

HINDI FILE



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY PRACTICE QUESTIONS

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **AUGUST 13, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

दैनिक अभ्यास प्रश्न - स्थैतिक भाग से

प्रश्न 1. ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. फैक्टरी प्रणाली का उद्भव न केवल तकनीकी आविष्कारों द्वारा सुगम हुआ था, बल्कि उत्पादन की एक केंद्रीकृत प्रणाली के तहत श्रमिकों, मशीनरी और पूंजी के संकेंद्रण द्वारा भी संभव हुआ था।
2. औद्योगिक क्रांति ने पारंपरिक कारीगरी उत्पादन की प्रासंगिकता को तुरंत समाप्त कर दिया क्योंकि यंत्रीकृत कारखाने अपनी शुरुआत से ही उत्पादन की हर शाखा में आर्थिक रूप से श्रेष्ठ बन गए थे।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल कथन 2
(b) दोनों कथन
(c) न तो कथन 1 और न ही 2
(d) केवल कथन 1

उत्तर: (d) केवल कथन 1

विस्तृत व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** फैक्टरी प्रणाली ने उत्पादन के एक मौलिक संगठनात्मक रूपांतरण का प्रतिनिधित्व किया। श्रमिकों, मशीनों, कच्चे माल और पूंजी को पर्यवेक्षण के तहत एक साझा कार्यस्थल पर एक साथ लाया गया। यंत्रीकृत कताई और बुनाई जैसे तकनीकी नवाचारों ने इस प्रक्रिया को मजबूत किया, लेकिन औद्योगिक क्रांति केवल आविष्कारों की कहानी नहीं थी; इसमें श्रम और पूंजी के संगठन में एक बड़ा परिवर्तन शामिल था।
- **कथन 2 गलत है:** कारीगरी (artisanal) उत्पादन से कारखाना उत्पादन में संक्रमण क्रमिक और असमान था। पारंपरिक कारीगर और घरेलू उत्पादन काफी समय तक कारखानों के साथ सह-अस्तित्व में रहे। कुशल शिल्पकारिता के माध्यम से कुछ विशेष वस्तुओं का उत्पादन जारी रहा क्योंकि मशीनीकरण हर क्षेत्र में समान रूप से लाभदायक नहीं था।

महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक अंतर:

तकनीकी परिवर्तन और संरचनात्मक रूपांतरण के बीच अंतर को समझना आवश्यक है। औद्योगीकरण में दोनों शामिल थे, लेकिन दोनों में से कोई भी समान रूप से या तुरंत घटित नहीं हुआ।

औद्योगिक क्रांति ने महत्वपूर्ण सामाजिक परिणाम भी उत्पन्न किए। फैक्टरी प्रणाली ने एक बड़े वेतन-आश्रित कार्यबल का निर्माण किया, शहरीकरण को गति दी और श्रम संगठन के नए रूपों को जन्म दिया। इसलिए, इसका महत्व मशीनरी से आगे बढ़कर वर्ग संबंधों, शहरी समाज, पूंजीवाद और श्रम राजनीति के क्षेत्रों तक फैला हुआ था।

प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक अनुक्रमण (Ecological Succession) के पारिस्थितिक महत्व की सबसे अच्छी व्याख्या करता है?

- (a) यह किसी भी गड़बड़ी-प्रेरित (disturbance-induced) परिवर्तन की संभावना के बिना एक पारिस्थितिकी तंत्र के दूसरे द्वारा स्थायी प्रतिस्थापन का प्रतिनिधित्व करता है।
- (b) यह समय के साथ किसी क्षेत्र की प्रजातियों की संरचना और सामुदायिक संरचना में अपेक्षाकृत अनुमानित, क्रमिक परिवर्तन का वर्णन करता है, जिसमें अक्सर पर्यावरणीय स्थितियों में बदलाव शामिल होता है।
- (c) यह केवल मिट्टी से पूरी तरह से रहित क्षेत्रों में होता है और इसलिए अनिवार्य रूप से मिट्टी बनाने में सक्षम अग्रणी (pioneer) प्रजातियों के साथ शुरू होता है।
- (d) यह विशेष रूप से पहले से स्थापित पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर प्रजातियों की प्रचुरता में मौसमी बदलावों को संदर्भित करता है।

उत्तर: (b)

विस्तृत व्याख्या:

पारिस्थितिक अनुक्रमण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से किसी जैविक समुदाय की संरचना और ढांचा समय के साथ बदलता है।

इस प्रक्रिया में आमतौर पर शामिल हैं:

अग्रणी (Pioneer) समुदाय → मध्यवर्ती चरण → अपेक्षाकृत स्थिर (Climax) समुदाय

यह प्रक्रिया **प्राथमिक अनुक्रमण (primary succession)** या **द्वितीयक अनुक्रमण (secondary succession)** के रूप में हो सकती है:

- **प्राथमिक अनुक्रमण** उस सतह पर शुरू होता है जहाँ जैविक समुदाय पहले से मौजूद नहीं था और जहाँ मिट्टी अनुपस्थित या काफी हद तक अविकसित होती है।
- **द्वितीयक अनुक्रमण** वहाँ होता है जहाँ कोई मौजूदा समुदाय बाधित हो गया है लेकिन मिट्टी और कुछ जैविक घटक बने रहते हैं।

इसलिए, अनुक्रमण अनिवार्य रूप से मिट्टी के निर्माण से ही शुरू नहीं होता है। यह एक ऐसी विशेषता है जो विशेष रूप से प्राथमिक अनुक्रमण से जुड़ी हुई है।

अनुक्रमण का महत्व यह है कि जीव स्वयं पर्यावरणीय स्थितियों को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, वनस्पति मिट्टी के गुणों, पोषक तत्वों की उपलब्धता, नमी और सूक्ष्म जलवायु (microclimate) को संशोधित कर सकती है, जिससे यह प्रभावित होता है कि कौन सी प्रजातियाँ बाद में स्थापित हो सकती हैं।

यह प्रक्रिया अपरिवर्तनीय (irreversible) भी नहीं है। आग, बाढ़, चक्रवात, मानवीय गतिविधियाँ, आक्रामक प्रजातियाँ और अन्य गड़बड़ियाँ अनुक्रमण के रास्तों को बदल सकती हैं या उन्हें पुनः प्रारंभ कर सकती हैं।

इस प्रकार, पारिस्थितिक अनुक्रमण को केवल मौसमी उतार-चढ़ाव या पूर्व निर्धारित पारिस्थितिकी तंत्र की ओर एक पूरी तरह से अपरिवर्तनीय प्रगति के बजाय सामुदायिक विकास और प्रतिस्थापन की एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए।

प्रश्न 3. किसी अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्र (External Sector) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. चालू खाता घाटे (Current Account Deficit) का अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि देश समग्र भुगतान संतुलन (Balance of Payments) में घाटे का सामना कर रहा है।
2. कोई देश तत्काल समग्र भुगतान संतुलन घाटे का सामना किए बिना शुद्ध पूंजी प्रवाह (net capital inflows) के माध्यम से चालू खाता घाटे का वित्तपोषण कर सकता है।
3. घरेलू मुद्रा के मूल्यहास (depreciation) से व्यापार संतुलन में सुधार हो सकता है, लेकिन इसका परिणाम आंशिक रूप से सापेक्ष कीमतों में बदलाव के प्रति निर्यात और आयात की मात्रा की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

उत्तर: (b) केवल दो

विस्तृत व्याख्या:

- **कथन 1 गलत है:** चालू खाता घाटा (CAD) का अनिवार्य रूप से यह अर्थ नहीं है कि समग्र भुगतान संतुलन (BoP) घाटे में है। कोई देश चालू खाता घाटे को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त पूंजी और वित्तीय प्रवाह आकर्षित कर सकता है।
- **कथन 2 सही है:** यदि पूंजी और वित्तीय प्रवाह चालू खाता घाटे को पर्याप्त रूप से वित्तपोषित करते हैं, तो समग्र बाह्य संतुलन प्रबंधनीय बना रह सकता है। यही कारण है कि बाह्य-क्षेत्र के स्थायित्व के लिए पूंजी प्रवाह की संरचना और स्थिरता महत्वपूर्ण है।
- **कथन 3 सही है:** मुद्रा का मूल्यहास विदेशी खरीदारों के लिए निर्यात को अपेक्षाकृत सस्ता और घरेलू स्तर पर आयात को अपेक्षाकृत अधिक महंगा बनाता है। हालाँकि, व्यापार संतुलन में सुधार निर्यात और आयात की मांग की मूल्य लोच (price elasticity of demand) पर निर्भर करता है। यह **मार्शल-लर्नर स्थिति (Marshall-Lerner condition)** से जुड़ा हुआ है।

एक और जटिलता **J-वक्र प्रभाव (J-curve effect)** है। मूल्यहास के तुरंत बाद, व्यापार संतुलन शुरू में बिगड़ सकता है क्योंकि मौजूदा आयात प्रतिबद्धताओं की कीमत पहले की मात्रा और अनुबंधों पर आधारित होती है। समय के साथ, यदि निर्यात और आयात की मात्रा बदली हुई सापेक्ष कीमतों पर पर्याप्त प्रतिक्रिया देती है, तो व्यापार संतुलन में सुधार हो सकता है।

इसलिए, यह प्रश्न निम्नलिखित के बीच अंतर स्पष्ट करता है:

चालू खाता संतुलन $\neq$ समग्र BoP संतुलन

और

मुद्रा का मूल्यहास $\neq$ व्यापार संतुलन में स्वतः सुधार

विदेशी विनिमय दर की गतिविधियों और बाह्य-क्षेत्र की स्थिरता का विश्लेषण करने में ये अंतर विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

प्रश्न 4. भारतीय राजनीति और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. दल-बदल विरोधी ढांचा (Anti-defection framework) विधायकों द्वारा दलीय संबद्धता में बदलाव के कुछ रूपों से उत्पन्न होने वाली राजनीतिक अस्थिरता को संबोधित करने का प्रयास करता है।
2. दल-बदल विरोधी कानून का अस्तित्व विधायिका के भीतर राजनीतिक पुनर्गठन (political realignment) की संभावना को पूरी तरह से समाप्त कर देता है।
3. दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष या सभापति की भूमिका संवैधानिक जांच के अधीन रही है क्योंकि दल-बदल विरोधी ढांचे के तहत फैसलों के विधायी संरचना पर महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं।
4. दल-बदल विरोधी कानून राजनीतिक दल के नेतृत्व के साथ किसी भी असहमति को विधायक की अयोग्यता का स्वचालित आधार बनाता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (b) केवल दो

विस्तृत व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से शामिल की गई दसवीं अनुसूची का उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल को रोकना और विधायिकाओं में स्थिरता को बढ़ावा देना था।
- **कथन 2 गलत है:** यह कानून राजनीतिक पुनर्गठन को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता है। निर्दिष्ट संवैधानिक शर्तों के तहत राजनीतिक दलों का विलय हो सकता है, और विधायक संवैधानिक रूप से अनुमत तंत्रों के माध्यम से भी राजनीतिक स्थितियों को बदल सकते हैं।
- **कथन 3 सही है:** दसवीं अनुसूची के तहत सदन के अध्यक्ष या सभापति को सौंपी गई न्यायनिर्णयन (adjudicatory) की भूमिका ने पर्याप्त संवैधानिक बहस पैदा की है। *किहोटो होलोहन बनाम ज़ाचिलहू* मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णायक प्राधिकारी के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की संभावना को स्वीकार करते हुए दल-बदल विरोधी कानून की व्यापक संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
- **कथन 4 गलत है:** पार्टी नेतृत्व के साथ केवल असहमति होने से ही स्वचालित रूप से अयोग्यता नहीं होती है। दसवीं अनुसूची राजनीतिक दल की सदस्यता को स्वेच्छा से छोड़ने या अनुसूची के तहत कवर की गई परिस्थितियों में पार्टी के निर्देश के विपरीत मतदान करने/अनुपस्थित रहने जैसी परिस्थितियों को निर्दिष्ट करती है।

गहरी संवैधानिक दुविधा दो प्रतिस्पर्धी उद्देश्यों के बीच है:

राजनीतिक स्थिरता और दलीय अनुशासन

बनाम

प्रतिनिधि स्वतंत्रता और विधायी विचार-विमर्श

दल-बदल विरोधी ढांचा इन उद्देश्यों को संतुलित करने का प्रयास करता है, हालांकि यह चिंता बनी हुई है कि अत्यधिक पार्टी नियंत्रण व्यक्तिगत विधायकों की विचार-विमर्श संबंधी भूमिका को कमजोर कर सकता है।

प्रश्न 5. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

कथन (A): उच्च ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम (Jet Streams) की घटना वातावरण में मजबूत क्षैतिज तापमान प्रवणता (horizontal temperature gradients) से गहराई से जुड़ी हुई है।

कारण I: एक मजबूत क्षैतिज तापमान प्रवणता ऊंचाई के साथ तदनुरूपी क्षैतिज दाब प्रवणता (horizontal pressure gradient) उत्पन्न करती है, जो मजबूत ऊपरी वायु पवन के विकास में योगदान देती है।

कारण II: जेट स्ट्रीम निचले वायुमंडलीय सीमा क्षेत्र (lower atmospheric boundary layer) तक सीमित हैं क्योंकि उनके निर्माण और रखरखाव के लिए पृथ्वी की सतह के साथ घर्षण आवश्यक है।

निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?

- (a) कथन (A) सही है, और कारण I तथा कारण II दोनों सही हैं, और दोनों कथन (A) की सही व्याख्या करते हैं।
- (b) कथन (A) सही है, कारण I सही है लेकिन कारण II गलत है।
- (c) कथन (A) गलत है, लेकिन कारण I और कारण II दोनों सही हैं।
- (d) कथन (A) सही है, लेकिन कारण I और कारण II दोनों गलत हैं।

उत्तर: (b)

विस्तृत व्याख्या:

कथन (A) सही है: जेट स्ट्रीम बहुत तेज हवाओं की संकीर्ण पट्टियां हैं जो मुख्य रूप से ऊपरी क्षोभमंडल (upper troposphere) में, विशेष रूप से क्षोभसीमा (tropopause) के पास चलती हैं। उनका निर्माण और तीव्रता मजबूत क्षैतिज तापीय विषमताओं (temperature contrasts) से गहराई से संबंधित है।

कारण I सही है:

एक मजबूत क्षैतिज तापमान प्रवणता ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव में अंतर पैदा करती है। तापीय-पवन संबंध (thermal-wind relationship) के माध्यम से, मजबूत क्षैतिज तापमान प्रवणता जियोस्ट्रोफिक पवन (geostrophic wind) की गति में मजबूत ऊर्ध्वाधर परिवर्तनों से जुड़ी होती है। यह क्षोभसीमा के पास बहुत तेज हवाओं के संकेंद्रण को समझाने में मदद करता है।

उदाहरण के लिए, ध्रुवीय अग्र जेट स्ट्रीम (polar front jet stream) अपेक्षाकृत ठंडी ध्रुवीय हवा और निचले अक्षांशों पर गर्म हवा के बीच तापमान के अंतर से मजबूती से जुड़ी हुई है।

कारण ॥ गलत है:

जेट स्ट्रीम निचले वायुमंडलीय सीमा क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं। वास्तव में, वे मुख्य रूप से ऊपरी-क्षोभमंडलीय परिघटनाएं हैं। पृथ्वी की सतह के साथ घर्षण ग्रहीय सीमा परत (planetary boundary layer) में अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण है, लेकिन उन ऊंचाइयों पर बहुत कम महत्वपूर्ण हो जाता है जहाँ जेट स्ट्रीम चलती हैं।

(इसलिए):

मजबूत क्षैतिज तापमान प्रवणता → ऊंचाई के साथ दाब-प्रवणता में भिन्नता → मजबूत ऊपरी-स्तरीय पवनें → जेट स्ट्रीम

यह प्रश्न सतही हवाओं (surface winds) और ऊपरी वायु परिसंचरण (upper-air circulation) के बीच एक महत्वपूर्ण UPSC अंतर को भी उजागर करता है। सतही घर्षण निकट-सतह की हवाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, जबकि जेट स्ट्रीम का बड़े पैमाने पर ढांचा मुख्य रूप से दबाव प्रवणता, पृथ्वी के घूर्णन और वायुमंडलीय तापमान वितरण द्वारा शासित होता है।

दैनिक अभ्यास प्रश्न – करंट अफेयर्स अनुभाग से

प्रश्न 1. 'समुद्र मंथन' (राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना / National Offshore Exploration Scheme) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है, जिसका उद्देश्य घरेलू अपतटीय हाइड्रोकार्बन अन्वेषण से जुड़े वित्तीय और तकनीकी जोखिमों को कम करना है।
2. इसकी वित्तीय सहायता विशेष रूप से अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग (exploratory drilling) तक सीमित है और इसका विस्तार भूकंपीय डेटा अधिग्रहण (seismic data acquisition) या सामान्य अपतटीय निकासी बुनियादी ढांचे (evacuation infrastructure) तक नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल कथन 2
- (b) दोनों कथन 1 और 2
- (c) न तो कथन 1 और न ही 2
- (d) केवल कथन 1

उत्तर: (d) केवल कथन 1

विस्तृत व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** समुद्र मंथन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2030-31 तक ₹84,084 करोड़ के परिव्यय की बात कही गई है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से गहरे पानी और सीमांत बेसिनों (deepwater and frontier basins) में अपतटीय तेल और गैस अन्वेषण को जोखिम-मुक्त (de-risk) और तेज करना है।
- **कथन 2 गलत है:** यह योजना एक व्यापक मूल्य-श्रृंखला (value-chain) दृष्टिकोण का पालन करती है। गहरे और अत्यधिक गहरे पानी में ड्रिलिंग के समर्थन के अलावा, यह निम्नलिखित का भी प्रावधान करती है:
 - बड़े पैमाने पर भूकंपीय डेटा का अधिग्रहण और व्याख्या;
 - सामान्य उत्पादन और निकासी बुनियादी ढांचा (evacuation infrastructure);
 - विनिर्माण और सेवा क्षेत्र (manufacturing and services zones); तथा
 - डिजिटल शासन और क्षमता निर्माण।

उल्लेखनीय है कि योजना में भूकंपीय डेटा और सामान्य निकासी बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित किए गए हैं।

विश्लेषणात्मक महत्व: सरकार केवल व्यक्तिगत ड्रिलिंग कार्यों को सब्सिडी देने के बजाय अपतटीय अन्वेषण के संपूर्ण जोखिम ढांचे को संबोधित करने का प्रयास कर रही है।

प्रश्न 2. 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना' (PM-SSY) मुख्य रूप से किसे बढ़ावा देना चाहती है?

- अनिवार्य नेट मीटरिंग के साथ आवासीय भवनों का बड़े पैमाने पर रूफटॉप सोलराइजेशन।
- जलाशयों और अन्य अंतर्देशीय जल निकायों पर फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक (Floating Solar PV) परियोजनाएं, ऊर्जा-भंडारण प्रणालियों (energy-storage systems) के साथ।
- छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से सौर ऊर्जा चालित सिंचाई पंप।
- भारत के तटीय आर्थिक क्षेत्र के साथ अपतटीय फ्लोटिंग पवन-सौर हाइब्रिड पार्क।

उत्तर: (b)

विस्तृत व्याख्या:

PM-SSY एक नवीकरणीय ऊर्जा योजना है जिसे जलाशयों, बांधों और अन्य अंतर्देशीय जल निकायों पर **फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक (FSPV)** परियोजनाओं के इर्द-गिर्द तैयार किया गया है। यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के तहत संचालित है, जिसमें सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) कार्यान्वयन एजेंसी है।

इस योजना का बजट परिव्यय ₹5,070 करोड़ है और इसका लक्ष्य FY 2026-27 से FY 2030-31 के दौरान 10,000 MWh ऊर्जा भंडारण के साथ 5,000 MW फ्लोटिंग सौर क्षमता जोड़ना है।

इसका महत्व केवल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से परे है। फ्लोटिंग सौर:

- दुर्लभ भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा को कम कर सकता है;

- सतह पर छायांकन (surface shading) के माध्यम से संभावित रूप से जल वाष्पीकरण को कम कर सकता है;
- मौजूदा जलाशयों के साथ सह-स्थान (co-location) की सुविधा प्रदान कर सकता है;
- भंडारण के साथ जुड़ने पर नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण में सुधार कर सकता है; तथा
- फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, मूरिंग सिस्टम, मॉड्यूल और बैटरी के घरेलू विनिर्माण के लिए मांग पैदा कर सकता है।

UPSC के लिए मुख्य ट्रेप: अंतर्देशीय जल निकायों पर फ्लोटिंग सौर को अपतटीय समुद्री सौर (offshore marine solar) के साथ भ्रमित न करें।

प्रश्न 3. पुनर्गठित 'खेलो इंडिया योजना' (Revamped Khelo India Scheme) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पुनर्गठित ढांचा एक संरचित मार्ग (structured pathway) बनाने का प्रयास करता है जो स्कूल-स्तरीय खेल विकास को उच्च-स्तरीय एथलीट प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धी उत्कृष्टता से जोड़ता है।
2. 'इमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट्स' (E-KIAs) की शुरुआत का उद्देश्य उन एथलीटों के समूह का विस्तार करना है जिन्हें संरचित पेशेवर और वैज्ञानिक सहायता प्राप्त होती है।
3. पुनर्गठित योजना अपने संस्थागत प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (National Centres of Excellence) तक सीमित करती है और राज्य-स्तरीय व अन्य विशेष प्रशिक्षण केंद्रों को बाहर करती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

उत्तर: (b) केवल दो

विस्तृत व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** पुनर्गठित ढांचा स्कूल स्तर की खेल भागीदारी और प्रतिभा पहचान से लेकर खेलो इंडिया केंद्रों और उच्च-प्रदर्शन प्रणालियों तक एक निरंतरता (continuum) स्थापित करने का प्रयास करता है। खेलो इंडिया फीडर स्कूल्स (KIFS) और खेलो इंडिया उत्कृष्ट विद्यालयों (KIUV) जैसी पहलों का उद्देश्य खेल प्रतिभाओं की शुरुआती पहचान और विकास को मजबूत करना है।
- **कथन 2 सही है:** मौजूदा खेलो इंडिया एथलीट्स (KIAs) के साथ 'इमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट्स' (E-KIAs) श्रेणी शुरू की गई है, जो संरचित एथलीट-विकास पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करती है।
- **कथन 3 गलत है:** प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र स्पष्ट रूप से केवल NCOEs तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत व्यापक है। इसमें शामिल हैं:
 - राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCOEs);

- खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र (KISCES);
- साई प्रशिक्षण केंद्र (SAI Training Centres - STCs); और
- सशस्त्र बलों द्वारा संचालित यूथ स्पोर्ट्स कंपनियां (YSCs)।

इसलिए, गहरा सुधार अलग-थलग खेल बुनियादी ढांचे से हटाकर एक एकीकृत एथलीट-विकास पाइपलाइन की ओर बदलाव है जिसमें स्कूल, राज्य, विशेष प्रशिक्षण, कोचिंग और खेल विज्ञान शामिल हैं।

प्रश्न 4. 'फावरा-UPI' (Favara-UPI) सीमा पार भुगतान गलियारे (Cross-Border Payment Corridor) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह मालदीव की फावरा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम (Favara Instant Payment System) को भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से जोड़ता है।
2. प्रारंभिक व्यवस्था मालदीव से UPI-सक्षम भारतीय बैंक खातों में रीयल-टाइम व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है।
3. यह गलियारा शुरू में विशेष रूप से मालदीव में भारतीय पर्यटकों द्वारा QR-आधारित मर्चेन्ट भुगतानों के लिए डिज़ाइन किया गया था।
4. इस व्यवस्था में मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (MMA), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) के बीच सहयोग शामिल है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (c) केवल तीन

विस्तृत व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** यह गलियारा मालदीव की फावरा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को भारत के UPI के साथ एकीकृत करता है।
- **कथन 2 सही है:** प्रारंभिक व्यवस्था रीयल-टाइम व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) हस्तांतरण को सक्षम बनाती है, जिससे धनराशि मालदीवियन रुफिया (MVR) से भारत में UPI-सक्षम भारतीय रुपये (INR) बैंक खातों में जा सकती है।
- **कथन 3 गलत है:** QR-आधारित मर्चेन्ट भुगतानों को भविष्य के विस्तार के रूप में पहचाना गया है। प्रारंभिक सुविधा व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) प्रेषण (remittances) पर केंद्रित है, जिसमें परिवार-रखरखाव और उपहार से संबंधित अनुमत प्रेषण शामिल हैं।

- **कथन 4 सही है:** संस्थागत सहयोग में मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (MMA), RBI, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) और भाग लेने वाले वित्तीय संस्थान शामिल हैं।

इसका व्यापक महत्व भारत की **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) कूटनीति** में निहित है। त्वरित-भुगतान प्रणालियों की सीमा-पार पारस्परिकता (interoperability) उपयोगकर्ताओं को पारंपरिक संवाददाता-बैंकिंग (correspondent-banking) तंत्रों पर विशेष रूप से निर्भर रहने की आवश्यकता के बिना लेनदेन लागत को कम कर सकती है और वित्तीय कनेक्टिविटी में सुधार कर सकती है।

प्रश्न 5. भारत में भीड़ नियंत्रण के लिए 'पेलेट गन' (Pellet Guns) के उपयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 'कम-घातक हथियारों' (less-lethal weapons) के रूप में उनका वर्गीकरण यह दर्शाता है कि भीड़ द्वारा उत्पन्न खतरे की प्रकृति और तीव्रता की परवाह किए बिना उनका उपयोग कानूनी और परिचालन रूप से अनुमत है।
2. आनुपातिकता के सिद्धांत (Principle of Proportionality) के अनुसार कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला बल खतरे की प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए और ऐसे बल की आवश्यकता समाप्त होने पर रुक जाना चाहिए।
3. पेलेट के व्यापक फैलाव (dispersion pattern) का पैटर्न इच्छित लक्ष्य के अलावा अन्य व्यक्तियों को चोट लगने का एक विशेष जोखिम पैदा करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

उत्तर: (b) केवल दो

विस्तृत व्याख्या:

- **कथन 1 गलत है:** पेलेट गन का "कम-घातक" के रूप में वर्णन करने का यह अर्थ नहीं है कि उनका उपयोग अप्रतिबंधित है। वर्तमान ढांचा आवश्यकता, आनुपातिकता और असाधारण/अंतिम उपाय (last-resort) के उपयोग पर बल देता है।
- **कथन 2 सही है:** आनुपातिकता का अर्थ है कि नियोजित बल खतरे के अनुरूप होना चाहिए और ऐसे बल की आवश्यकता समाप्त हो जाने के बाद जारी नहीं रहना चाहिए। परिचालन ढांचा पेलेट गन को बल के क्रमिक वृद्धि (graded escalation) के भीतर रखता है।
- **कथन 3 सही है:** एक एकल कार्ट्रिज बड़ी संख्या में पेलेट छोड़ सकता है जो एक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाते हैं। इससे राहगीरों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को चोट लगने की संभावना बनती है और यह उनके उपयोग से जुड़ी प्रमुख मानव-अधिकार चिंताओं में से एक है।

UPSC-स्तरीय वैचारिक मुद्दा: यहाँ मुख्य अंतर "कम-घातक" (less-lethal) और "अहानिकर" (non-harmful) के बीच है। कम-घातक हथियार पारंपरिक आग्नेयास्त्रों की तुलना में घातकता की संभावना को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन वे फिर भी गंभीर या स्थायी चोटों का कारण बन सकते हैं। इसलिए, उनकी तैनाती आवश्यकता, आनुपातिकता और परिचालन सुरक्षा उपायों के अधीन बनी रहती है।

प्रश्न 6. हाल ही में खबरों में रहे 'ब्रॉड पीक' (Broad Peak) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है।
2. यह K2 के अत्यधिक निकट स्थित है।
3. यह नेपाल के पूर्व में हिमालय श्रृंखला में स्थित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b) केवल 1 और 2

विस्तृत व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** ब्रॉड पीक काराकोरम पर्वत श्रृंखला (Karakoram Range) में स्थित है।
- **कथन 2 सही है:** यह K2 से लगभग 8 किमी दक्षिण-पूर्व में स्थित है, जो मानचित्र-आधारित प्रश्नों के लिए इन दो चोटियों के बीच स्थानिक संबंध को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।
- **कथन 3 गलत है:** ब्रॉड पीक नेपाल के पूर्व में हिमालय श्रृंखला में नहीं है। यह व्यापक हिमालय पर्वत प्रणाली के उत्तर-पश्चिमी भाग में काराकोरम क्षेत्र से संबंधित है।

ब्रॉड पीक की ऊंचाई लगभग 8,051 मीटर है और इसे दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में गिना जाता है। यह K2 के करीब **गैशरब्रम पर्वतसमूह (Gasherbrum massif)** क्षेत्र में स्थित है।

मानचित्र-आधारित मेमोरी एड (Map-based memory aid):

काराकोरम (Karakoram) → K2 → ब्रॉड पीक (Broad Peak) → गैशरब्रम पर्वतसमूह (Gasherbrum massif)

दैनिक अभ्यास हेतु विषय आधारित प्रश्न

GS पेपर I: भारतीय समाज / आधुनिक भारतीय इतिहास

Q.1 “अठारहवीं शताब्दी के भारत में किसानों, जमींदारों और औपनिवेशिक राज्य के बीच संबंध न तो पूर्ण शोषण से चिह्नित थे और न ही सामंजस्यपूर्ण सहयोग से, बल्कि यह बातचीत और प्रतियोगिता (negotiation and contestation) की एक जटिल प्रक्रिया थी।” चर्चा कीजिए।

NCERT संदर्भ: भारतीय इतिहास के कुछ विषय – भाग II, कक्षा XII — अध्याय 8, किसान, जमींदार और राज्य: कृषि समाज और मुगल साम्राज्य (लगभग 16वीं-17वीं शताब्दियां)।

मॉडल उत्तर (Model Answer)

पूर्व-औपनिवेशिक भारत का कृषि ढांचा केवल शोषक राज्य और शोषित किसानों के बीच का द्विआधारी (binary) संबंध नहीं था। इसमें किसान, जमींदार, स्थानीय बिचौलिए, ग्रामीण समुदाय और मुगल राज्य शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक के पास आर्थिक और सामाजिक शक्ति के अलग-अलग रूप थे। इसलिए, यह संबंध सहयोग और प्रतियोगिता (प्रतिस्पर्धा) दोनों से चिह्नित था।

मुगल साम्राज्य कृषि उत्पादन पर बहुत अधिक निर्भर था क्योंकि भू-राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। राज्य ने एक विस्तृत प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से कृषि उत्पादन का आकलन करने और राजस्व एकत्र करने का प्रयास किया। हालाँकि, राज्य आम तौर पर सीधे भूमि पर खेती नहीं करता था। वास्तविक उत्पादन प्रक्रिया उन किसानों पर निर्भर थी जिनके पास पारंपरिक अधिकार और खेती का ज्ञान था।

जमींदारों का स्थान एक बिचौलिए लेकिन शक्तिशाली वर्ग का था। वे भूमि पर वंशानुगत अधिकार रखते थे, राजस्व एकत्र करते थे और गांवों में काफी प्रभाव रखते थे। उनका अधिकार केवल औपचारिक राज्य मान्यता से ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिति, संसाधनों पर नियंत्रण और स्थानीय समुदायों के साथ संबंधों से भी प्राप्त होता था।

परिणामस्वरूप, जमींदारों और किसानों के बीच संबंध द्वैधवृत्ति (ambivalent) वाले थे। जमींदार किसानों से संसाधन एकत्र कर सकते थे, लेकिन वे सुरक्षा प्रदान भी करते थे, खेती को सुगम बनाते थे और कृषि बस्तियों के विस्तार में भाग लेते थे। इसलिए उनके हित हमेशा साम्राज्यिक राज्य के हितों से मेल नहीं खाते थे।

किसान स्वयं निष्क्रिय पीड़ित नहीं थे। ऐतिहासिक साक्ष्य दर्शाते हैं कि उनके पास पर्याप्त स्वायत्तता और विवेकशील एजेंसी (agency) थी। वे पलायन कर सकते थे, अत्यधिक मांगों का विरोध कर सकते थे, फसल पैटर्न बदल सकते थे और अत्यधिक परिस्थितियों में सामूहिक विद्रोह में भाग ले सकते थे। इसलिए, किसान प्रतिरोध राज्य के राजस्व निष्कर्षण की सीमाओं का एक महत्वपूर्ण संकेतक बन सकता था।

राज्य की भूमिका

मुगल राज्य ने कृषि उत्पादकता को पूरी तरह से नष्ट किए बिना राजस्व को अधिकतम करने का प्रयास किया। अत्यधिक निष्कर्षण से खेती कम हो सकती थी और परिणामस्वरूप भविष्य का राजस्व घट सकता था। इसने अल्पकालिक राजस्व अधिकतमीकरण और दीर्घकालिक कृषि स्थिरता के बीच एक अंतर्निहित तनाव पैदा किया।

नकदी फसलों के विस्तार ने ग्रामीण उत्पादन को व्यापक बाजारों से भी जोड़ा। व्यवसायीकरण ने समृद्ध किसानों और व्यापारियों के लिए अवसर बढ़ाए, लेकिन साथ ही यह गरीब काशतकारों को ऋणग्रस्तता और बाजार के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बना सकता था।

इस प्रकार, कृषि संबंध बातचीत, निर्भरता, निष्कर्षण और प्रतिरोध द्वारा चिह्नित थे।

इस ऐतिहासिक अनुभव का महत्व यह दर्शाने में निहित है कि ग्रामीण समाज को एक साधारण शोषक-पीड़ित ढांचे के माध्यम से नहीं समझा जा सकता है। शक्ति कई स्तरों पर वितरित की गई थी, और किसानों ने एजेंसी की अलग-अलग डिग्री बनाए रखी।

इसलिए, कृषि प्रणाली राज्य की राजस्व आवश्यकताओं, जमींदारी हितों और किसान उत्पादन के बीच एक नाजुक संतुलन के माध्यम से कायम रही। जब भी यह संतुलन अत्यधिक निष्कर्षण, राजनीतिक अस्थिरता या पर्यावरणीय तनाव से बाधित होता था, तो प्रतिरोध और संघर्ष की संभावना बढ़ जाती थी।

GS पेपर II: शासन व्यवस्था (Governance)

Q.2 “एक संघीय लोकतंत्र में शासन की प्रभावशीलता केवल शक्तियों के संवैधानिक आवंटन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि अंतर-सरकारी समन्वय की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है।” भारतीय संघवाद के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

NCERT संदर्भ: स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीति, कक्षा XII — अध्याय 7, क्षेत्रीय आकांक्षाएं; कार्यरत भारतीय संविधान, कक्षा XI — संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध।

मॉडल उत्तर (Model Answer)

भारत की संघीय प्रणाली शक्तियों के संवैधानिक विभाजन को अपेक्षाकृत मजबूत संघ (केंद्र) के साथ जोड़ती है। हालाँकि, इतने विविध देश में प्रभावी शासन केवल औपचारिक संवैधानिक आवंटन पर निर्भर नहीं हो सकता। इसके लिए संघ और राज्यों के बीच निरंतर सहयोग, परामर्श, समन्वय और संस्थागत संवाद की आवश्यकता होती है।

संविधान सातवीं अनुसूची के तहत संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के माध्यम से विधायी शक्तियों का वितरण करता है। वित्तीय संबंध, प्रशासनिक उत्तरदायित्व और वित्त आयोग जैसे संवैधानिक तंत्र केंद्र-राज्य संबंधों को और अधिक सुव्यवस्थित करते हैं। फिर भी, कई समकालीन नीतिगत चुनौतियाँ—जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रवासन, आंतरिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और आपदा प्रबंधन—क्षेत्रीय सीमाओं को पार करती हैं।

यह स्थिति **सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism)** को अनिवार्य बनाती है।

उदाहरण के लिए, GST परिषद राजकोषीय संघवाद में एक महत्वपूर्ण संस्थागत प्रयोग का प्रतिनिधित्व करती है। यह कराधान के मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए संघ और राज्यों को एक साथ लाती है। इसी तरह, वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण को सुगम बनाता है, जिससे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन को संबोधित किया जाता है।

अंतर-राज्य परिषद, क्षेत्रीय परिषदें और अन्य समन्वय तंत्र भी संवाद और संघर्ष समाधान में योगदान दे सकते हैं।

हालाँकि, भारतीय संघवाद को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

1. **राजकोषीय विषमता (Fiscal Asymmetry):** यह संघ को पर्याप्त वित्तीय प्रभाव प्रदान करती है। राज्य अक्सर तर्क देते हैं कि उनके स्वतंत्र राजस्व-उत्पादन क्षमता की तुलना में उनके व्यय के उत्तरदायित्व अधिक तेज़ी से बढ़े हैं।

2. **प्रशासनिक व राजनीतिक तनाव:** राज्यपाल की भूमिका, केंद्र प्रायोजित योजनाओं, जांच एजेंसियों, प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र और अनुच्छेद 356 के उपयोग से संबंधित विवादों ने समय-समय पर केंद्र-राज्य तनाव उत्पन्न किए हैं।
3. **क्षेत्रीय आकांक्षाएं:** ये अधिक स्वायत्तता की मांग पैदा कर सकती हैं। भाषाई पुनर्गठन का अनुभव दर्शाता है कि भारत का संघीय ढांचा ऐतिहासिक रूप से कठोर केंद्रीकरण के बजाय समायोजन के माध्यम से विकसित हुआ है।

शासन का आयाम (Governance Dimension)

प्रभावी संघीय शासन के लिए ऐसे संस्थागत तंत्रों की आवश्यकता होती है जो राजनीतिक असहमति को संरचित वार्ता (structured negotiation) में परिवर्तित करें।

निम्नलिखित उपाय संघीय शासन को मजबूत कर सकते हैं:

- अंतर-राज्य परिषद की नियमित बैठकें।
- राज्यों को प्रभावित करने वाले प्रमुख विधायी और नीतिगत निर्णयों से पहले उनसे अधिक परामर्श।
- राजकोषीय पूर्वानुमान क्षमता (fiscal predictability) को मजबूत करना।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं का युक्तीकरण (rationalisation)।
- स्थानीय सरकारों का अधिक कार्यात्मक और वित्तीय सशक्तीकरण।
- अंतर-राज्यीय विवादों को सुलझाने के लिए संस्थागत तंत्र।
- राज्यपालों से संबंधित संवैधानिक परंपराओं का सम्मान।

पुंछी आयोग और सरकारी आयोग दोनों ने केंद्र-राज्य संबंधों में परामर्श और सहकारी कार्यप्रणाली के महत्व पर बल दिया है।

साथ ही, सहकारी संघवाद का तात्पर्य राजनीतिक असहमति की अनुपस्थिति नहीं है। एक स्वस्थ संघ असहमति की अनुमति देता है जबकि ऐसे संस्थान प्रदान करता है जिनके माध्यम से असहमतियों पर बातचीत की जा सकती है।

इसलिए, भारतीय संघवाद को केवल विषयों के संवैधानिक विभाजन के रूप में नहीं बल्कि समायोजन की एक सतत राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए। शासन की गुणवत्ता अंततः इस बात पर निर्भर करती है कि संघ और राज्य एक-दूसरे को प्रतिस्पर्धी प्राधिकरणों के रूप में देखते हैं या पूरक संवैधानिक साझेदारों के रूप में।

GS पेपर III: अर्थव्यवस्था (Economy)

Q.3 “भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए, बाह्य-क्षेत्र की स्थिरता (external-sector stability) विनिमय-दर स्थिरता (exchange-rate stability) का पर्याय नहीं है।” इस अंतर को स्पष्ट कीजिए और भारत के बाह्य-क्षेत्र के लचीलेपन (resilience) को निर्धारित करने वाले कारकों का परीक्षण कीजिए।

NCERT संदर्भ: समष्टि अर्थशास्त्र - एक परिचय, कक्षा XII — अध्याय 6, खुली अर्थव्यवस्था - समष्टि अर्थशास्त्र।

मॉडल उत्तर (Model Answer)

बाह्य-क्षेत्र की स्थिरता का तात्पर्य अवांछनीय बाह्य असंतुलन उत्पन्न किए बिना, अचानक पूंजी-प्रवाह के विपरीत होने के जोखिम के बिना या विदेशी मुद्रा संसाधनों पर निरंतर दबाव के बिना अपने अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन को प्रबंधित करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता से है। इसलिए यह केवल एक स्थिर विनिमय दर बनाए रखने की तुलना में बहुत अधिक व्यापक है।

विनिमय दर केवल एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के संदर्भ में कीमत का प्रतिनिधित्व करती है। आवश्यक नहीं कि मुद्रा का मूल्यहास (depreciation) या मूल्यवृद्धि (appreciation) बाह्य-क्षेत्र की अस्थिरता का संकेत दे। वास्तव में, एक लचीली विनिमय दर कभी-कभी मुद्रा को वैश्विक परिस्थितियों में परिवर्तनों के साथ समायोजित होने की अनुमति देकर 'शॉक एब्जॉर्बर' (shock absorber) के रूप में कार्य कर सकती है।

भारत का बाह्य क्षेत्र कई घटकों से प्रभावित होता है:

1. **चालू खाता (Current Account):** चालू खाते में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, आय प्रवाह और हस्तांतरण शामिल हैं। भारत का व्यापार संतुलन संरचनात्मक रूप से आयातित कच्चे तेल, सोने और कुछ मध्यवर्ती व पूंजीगत वस्तुओं पर इसकी निर्भरता से प्रभावित होता है। साथ ही, भारत के पास सेवाओं के निर्यात में महत्वपूर्ण ताकत है, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक सेवाओं और पेशेवर सेवाओं में।
2. **पूंजी और वित्तीय प्रवाह (Capital and Financial Flows):** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), पोर्टफोलियो निवेश और बाह्य ऋण चालू खाते के घाटे को वित्तपोषित कर सकते हैं और निवेश का समर्थन कर सकते हैं। हालाँकि, पोर्टफोलियो प्रवाह अस्थिर हो सकता है और वैश्विक वित्तीय तनाव के दौरान तेज़ी से वापस आ सकता है। इसलिए, पूंजी आवक की गुणवत्ता और स्थिरता उतनी ही मायने रखती है जितना कि उसका परिमाण।
3. **विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign-Exchange Reserves):** पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बाह्य झटकों के खिलाफ एक बफर प्रदान करता है। वे विश्वास बढ़ाते हैं और मौद्रिक प्राधिकरण को बाजार की अव्यवस्थित स्थितियों को प्रबंधित करने की अनुमति देते हैं।
4. **विनिमय-दर लचीलापन (Exchange-Rate Flexibility):** रुपये का मूल्यहास निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार कर सकता है, लेकिन यह साथ ही आयात की घरेलू-मुद्रा लागत को बढ़ा सकता है। अंतिम प्रभाव व्यापार की संरचना और मूल्य लोच (price elasticities) पर निर्भर करता है। यह संबंध J-वक्र प्रभाव (J-curve effect) से भी जटिल होता है, जिसके तहत मात्रा में समायोजन होने से पहले मूल्यहास के बाद व्यापार संतुलन शुरू में खराब हो सकता है।
5. **वैश्विक संवेदनशीलताएं (Global Vulnerabilities):** भारत निम्नलिखित के प्रति संवेदनशील बना हुआ है:
 - कच्चे तेल की कीमतों में उछाल;
 - भू-राजनीतिक व्यवधान;
 - वैश्विक ब्याज दर में बदलाव;
 - आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान;
 - अचानक पूंजी की निकासी;
 - प्रमुख निर्यात बाजारों में मंदी।

आगे की राह (Way Forward)

बाह्य लचीलेपन के लिए किसी विशेष विनिमय-दर स्तर का बचाव करने से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। भारत को:

- निर्यात उत्पादों और गंतव्यों का विविधीकरण करना चाहिए;
- घरेलू विनिर्माण को गहरा करना चाहिए;
- आयातित ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भरता कम करनी चाहिए;
- सेवा निर्यात को मजबूत करना चाहिए;
- स्थिर दीर्घकालिक पूंजी को आकर्षित करना चाहिए;
- पर्याप्त भंडार बनाए रखना चाहिए;
- रसद (logistics) और व्यापार बुनियादी ढांचे में सुधार करना चाहिए;
- विवेकपूर्ण बाह्य ऋण नीति अपनानी चाहिए।

मुख्य अंतर:

- **विनिमय-दर स्थिरता** $\rightarrow$ मुद्रा की कीमत में स्थिरता।
- **बाह्य-क्षेत्र की स्थिरता** $\rightarrow$ संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति की संधारणीयता (sustainability)।

इसलिए भारत को किसी विशेष विनिमय-दर स्तर को स्थायी रूप से बनाए रखने का प्रयास करने के बजाय बाह्य झटकों को अवशोषित करने में सक्षम अर्थव्यवस्था के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक लचीली मुद्रा, विविधीकृत निर्यात, स्थिर पूंजी प्रवाह और पर्याप्त भंडार मिलकर एक अधिक लचीला बाह्य क्षेत्र बनाते हैं।

GS पेपर IV: नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि

Q.4 “लोक प्रशासन में नैतिक निर्णय लेने के लिए अक्सर एक निरपेक्ष सही और एक निरपेक्ष गलत के बीच चयन करने के बजाय प्रतिस्पर्धी मूल्यों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है।” उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए।

संदर्भ ढांचा: UPSC GS पेपर IV — नैतिक निर्णय निर्माण, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सत्यनिष्ठा और लोक सेवा मूल्य; कार्यरत भारतीय संविधान, कक्षा XI।

मॉडल उत्तर (Model Answer)

लोक प्रशासन अक्सर ऐसी स्थितियों में काम करता है जहाँ प्रतिस्पर्धी नैतिक मूल्य आपस में टकराते हैं। एक प्रशासक को गोपनीयता/निजता के साथ पारदर्शिता, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के साथ करुणा, पर्यावरणीय संरक्षण के साथ विकास और संवैधानिक तटस्थता के साथ राजनीतिक प्रतिक्रियाशीलता को संतुलित करना पड़ सकता है। इसलिए, नैतिक निर्णय लेने को हमेशा स्पष्ट रूप से सही या गलत विकल्प की पहचान करने तक सीमित नहीं किया जा सकता है।

सरकारी भूमि पर स्थित एक अवैध बस्ती के विध्वंस से निपटने वाले जिला प्रशासन पर विचार करें। कानून के शासन के दृष्टिकोण से बेदखली आवश्यक हो सकती है। हालाँकि, करुणा और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से, पुनर्वास के बिना तत्काल विध्वंस से संवेदनशील परिवारों को भारी कठिनाई हो सकती है।

इसलिए नैतिक चुनौती केवल यह नहीं है:

“क्या अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए?”

बल्कि यह है:

“अनावश्यक मानवीय पीड़ा को कम करते हुए कानून के शासन को कैसे बनाए रखा जा सकता है?”

एक नैतिक रूप से परिपक्व प्रशासक कानूनी नोटिस दे सकता है, सत्यापन कर सकता है, संवेदनशील परिवारों की पहचान कर सकता है, पुनर्वास का समन्वय कर सकता है और फिर कानून लागू कर सकता है।

इसी तरह, पर्यावरणीय शासन में अक्सर विकास और पारिस्थितिक संधारणीयता के बीच संघर्ष शामिल होता है। एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना रोजगार और कनेक्टिविटी उत्पन्न कर सकती है लेकिन वनों या स्थानीय आजीविका को खतरे में डाल सकती है। नैतिक प्रतिक्रिया को स्वतः ही विकास या संरक्षण में से किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय, प्रशासक को विकल्पों, पर्यावरणीय प्रभावों, पुनर्वास आवश्यकताओं और दीर्घकालिक जनहित का परीक्षण करना चाहिए।

शामिल नैतिक सिद्धांत

कई मूल्य ऐसे निर्णयों का मार्गदर्शन कर सकते हैं:

- **सत्यनिष्ठा (Integrity):** संवैधानिक और व्यावसायिक सिद्धांतों के प्रति वफादार रहना।
- **निष्पक्षता (Impartiality):** पक्षपात से बचना।
- **वस्तुनिष्ठता (Objectivity):** दबाव के बजाय साक्ष्यों पर निर्भर रहना।
- **सहानुभूति (Empathy):** निर्णयों के मानवीय परिणामों को समझना।
- **न्याय (Justice):** लाभों और बोझों का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करना।
- **जवाबदेही (Accountability):** निर्णयों की जिम्मेदारी स्वीकार करना।
- **करुणा (Compassion):** अनावश्यक कष्टों को रोकना।

वैधता (Legality) और नैतिकता (Morality) के बीच का अंतर भी महत्वपूर्ण है। कोई कार्रवाई तकनीकी रूप से किसी नियम का अनुपालन कर सकती है लेकिन फिर भी एक अन्यायपूर्ण परिणाम दे सकती है। इसके विपरीत, एक स्पष्ट रूप से दयालु कार्रवाई कानूनी आवश्यकताओं का उल्लंघन कर सकती है और मनमाना प्रशासन बना सकती है।

इसलिए, नैतिक शासन के लिए केवल व्यक्तिगत नैतिकता ही नहीं, बल्कि **संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality)** की आवश्यकता होती है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence) की भूमिका

भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रशासकों को किसी विशेष समूह से भावनात्मक रूप से प्रभावित हुए बिना विभिन्न हितधारकों की चिंताओं को पहचानने में मदद कर सकती है। सहानुभूति समझ में सुधार कर सकती है, जबकि आत्म-नियमन (self-regulation) जल्दबाजी वाले निर्णयों को रोकता है।

हालाँकि, सहानुभूति को कानून और निष्पक्षता की सीमाओं के भीतर काम करना चाहिए। चयनात्मक करुणा स्वयं भेदभावपूर्ण बन सकती है।

आगे की राह (Way Forward)

नैतिक निर्णय लेने को निम्नलिखित के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है:

- स्पष्ट आचार संहिता;
- पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया;
- हितधारक परामर्श;
- नैतिक प्रभाव मूल्यांकन;
- संस्थागत जांच और संतुलन;
- तर्कसंगत लिखित आदेश;
- संवैधानिक मूल्यों और भावनात्मक बुद्धिमत्ता में प्रशिक्षण।

अंततः, नैतिक प्रशासन हर स्थिति में सही समाधान खोजने के बारे में नहीं है। यह प्रतिस्पर्धी मूल्यों को व्यवस्थित रूप से संतुलित करने, परिणामों पर विचार करने और संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति वफादार रहने के बाद कार्रवाई का सबसे न्यायसंगत मार्ग चुनने के बारे में है।

समसामयिकी (Current Affairs): पश्चिमी घाट संरक्षण एवं पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र विवाद

Q.5 “पश्चिमी घाट के हिस्सों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करने पर लंबे समय से चल रही बहस यह दर्शाती है कि भारत में पर्यावरणीय शासन जितना जैव विविधता संरक्षण का प्रश्न है, उतना ही संघवाद और आजीविका सुरक्षा का भी प्रश्न है।” समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

मॉडल उत्तर (Model Answer)

पश्चिमी घाट भारत के सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक परिदृश्यों में से हैं, जिन्हें असाधारण जैव विविधता, उच्च स्थानिकता (endemism), वन पारिस्थितिकी तंत्र, जलग्रहण कार्य और भारतीय मानसून पर प्रभाव के लिए जाना जाता है। फिर भी पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) स्थापित करने के प्रयास विवादास्पद रहे हैं क्योंकि संरक्षण के उद्देश्य आजीविका, विकास, संघवाद और स्थानीय भागीदारी के प्रश्नों के साथ प्रतिच्छेद करते हैं।

इस बहस की बौद्धिक जड़ें माधव गाडगिल की अध्यक्षता वाले 'वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल' (WGEEP) और के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाले बाद के 'हायर लेवल वर्किंग ग्रुप' (HLWG) में हैं। गाडगिल दृष्टिकोण ने अपेक्षाकृत व्यापक और अधिक श्रेणीबद्ध पारिस्थितिक संरक्षण ढांचे की वकालत की, जबकि कस्तूरीरंगन दृष्टिकोण ने पारिस्थितिक रूप से मूल्यवान प्राकृतिक परिदृश्यों पर अधिक केंद्रित ध्यान देने की मांग की। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बाद में कई मसौदा अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिस पर राज्य सरकारों और स्थानीय हितधारकों ने अपने प्रभावों को लेकर चिंताएं जताई हैं।

यह बहस हाल के वर्षों में फिर से तेज हुई है, जिसमें केंद्र ने छह पश्चिमी घाट राज्यों में लगभग 56,825 वर्ग किलोमीटर को ESA के रूप में प्रस्तावित करते हुए मसौदा अधिसूचना जारी की है। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में स्थानीय विरोध इस चिंता पर केंद्रित रहा है कि ESA टैग विकास को प्रतिबंधित कर सकता है और आजीविका को प्रभावित कर सकता है।

संरक्षण क्यों आवश्यक है?

मजबूत सुरक्षा के लिए पारिस्थितिक कारण अत्यधिक अकाट्य हैं।

पश्चिमी घाट:

- उच्च स्तर की स्थानिक जैव विविधता धारण करते हैं;

- प्रमुख नदी प्रणालियों को नियंत्रित करते हैं;
- वर्षा पैटर्न को प्रभावित करते हैं;
- वनों और वन्यजीव आवासों को आश्रय देते हैं;
- लाखों लोगों को पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं;
- महत्वपूर्ण कार्बन और जल भंडार के रूप में कार्य करते हैं।

हाल की वैज्ञानिक खोजें इसके पारिस्थितिक महत्व को सुदृढ़ करती हैं। (उदाहरण के लिए, पश्चिमी घाट में लाइकेन-फॉर्मिंग कवक की नई प्रजातियों की खोज यह दर्शाती है कि महत्वपूर्ण जैविक विविधता का दस्तावेजीकरण अभी भी अधूरा है।)

साथ ही, अनियंत्रित निर्माण, खनन, उत्खनन (quarrying), बुनियादी ढांचे का विस्तार, वनों की कटाई और भूमि-उपयोग में बदलाव पारिस्थितिक संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, जिसमें भूस्खलन और जलग्रहण क्षेत्र के जोखिम शामिल हैं।

विरोध क्यों मौजूद है?

ESA पदनाम को अक्सर स्थानीय स्तर पर निम्नलिखित के लिए एक खतरे के रूप में देखा जाता है:

- कृषि आजीविका;
- आवास और बस्ती का विस्तार;
- बुनियादी ढांचा विकास;
- उत्खनन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियां;
- भूमि-उपयोग का लचीलापन।

इसलिए चुनौती केवल 'पर्यावरण बनाम विकास' की नहीं है। कई स्थानीय समुदाय स्वयं कृषि, जल और आजीविका के लिए स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर हैं।

संघवाद का आयाम (Federalism Dimension)

पश्चिमी घाट ESA मुद्दे में छह राज्य शामिल हैं — गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु।

पर्यावरणीय शासन संवैधानिक रूप से सरकार के कई स्तरों पर साझा किया जाता है, जबकि भूमि, कृषि, स्थानीय विकास और आजीविका की चिंताएं काफी हद तक राज्य और स्थानीय हितों से जुड़ी होती हैं। नतीजतन, एक समान ऊपर से थोपा गया (top-down) मॉडल राजनीतिक प्रतिरोध उत्पन्न कर सकता है।

इसलिए समाधान **सहकारी पर्यावरणीय संघवाद (Cooperative Environmental Federalism)** पर आधारित होना चाहिए।

आगे की राह (Way Forward)

एक संधारणीय ढांचे में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

1. **वैज्ञानिक ज़ोनिंग (Scientific Zoning):** पश्चिमी घाट के हर हिस्से में समान प्रतिबंधों की आवश्यकता नहीं है। पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण परिदृश्यों को मजबूत सुरक्षा मिलनी चाहिए।

2. **स्थानीय भागीदारी (Local Participation):** ग्राम पंचायतों, स्थानीय समुदायों, किसानों और आदिवासी समूहों को निर्णय लेने में सार्थक रूप से भाग लेना चाहिए।
3. **प्रोत्साहन-आधारित संरक्षण (Incentive-based Conservation):** राज्यों और स्थानीय समुदायों को पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बनाए रखने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन मिलने चाहिए।
4. **सतत विकास (Sustainable Development):** पारिस्थितिक वहन क्षमता (carrying capacity) के अनुकूल गतिविधियों को अत्यधिक विनाशकारी गतिविधियों से अलग किया जाना चाहिए।
5. **संचयी-प्रभाव मूल्यांकन (Cumulative-impact Assessment):** परियोजनाओं का मूल्यांकन न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि परिदृश्य, जलग्रहण क्षेत्रों और जैव विविधता पर उनके संयुक्त प्रभाव के लिए भी किया जाना चाहिए।
6. **आपदा-लचीलापन दृष्टिकोण (Disaster-resilience Approach):** भूमि-उपयोग योजना में भूस्खलन, बाढ़ और जलवायु-जोखिम मूल्यांकन को शामिल किया जाना चाहिए।

पश्चिमी घाट विवाद इस प्रकार पर्यावरणीय शासन के एक बड़े सिद्धांत को दर्शाता है: संरक्षण तब तक टिकाऊ नहीं हो सकता जब तक कि स्थानीय समुदाय इसे बाहर से थोपे गए प्रतिबंध के रूप में देखते हैं, जबकि विकास तब तक संधारणीय नहीं हो सकता जब पारिस्थितिक वहन क्षमता की उपेक्षा की जाती है।

भारत को वैज्ञानिक साक्ष्य + संघीय परामर्श + स्थानीय भागीदारी + आजीविका सुरक्षा + पारिस्थितिक सीमाएं को जोड़ने वाले मॉडल की आवश्यकता है। ऐसा दृष्टिकोण पश्चिमी घाट को एक आवर्ती केंद्र-राज्य संघर्ष से सहकारी और सहभागितापूर्ण पर्यावरणीय शासन के मॉडल में बदल सकता है।

